PRESS NOTE **Dated: September 08, 2025**

- **UPERC determines Load Despatch Centre (LDC) charges for FY 2025-26 on the Petition filed by UPSLDC**
  - **LDC charges determined at Rs. 678.09/MW/Month as against demand of Rs. 776.09/MW/Month**
  - **Gives directions for technical upgradation and checking vulnerability against cyber attacks**
    - **Provides incentives for skill upgradation & certification of employed personnels**

1. Uttar Pradesh State Load Despatch Centre i.e. UPSLDC had filed Petition No. 2231 of 2025 for True Up of FY 2023-24, Annual Performance Review (APR) for FY 2024-25 & Aggregate Revenue Requirement (ARR) & SLDC Charges for FY 2025-26. The same was admitted by the Commission on July 24, 2025.

   Subsequently, the Commission after due process of Public consultation and after conducting Public hearing on August 20, 2025 has determined Load Despatch Centre (LDC) charges through Tariff Order for FY 2025-26, which is being issued on September 08, 2025.

2. Key highlights of Tariff Order are as follow:

   (i) The Commission has approved the monthly LDC Charges of Rs. 678.09 / MW/ Month for FY 2025-26. The Commission has considered 58694 MW of contracted / tied up capacity of users who are availing long/medium term Open access. The details are shown in the Table below:

APPROVED LDC CHARGES FOR FY 2025-26

Particulars	Units	FY 2025-26	
		Claimed by Petitioner	Approved by Commission
Annual Revenue Requirement (ARR) for FY 2025-26 **(A)**	Rs. Lakh	2,617.52	2,611.84
Adjustment Gap of FY 2023-24 & FY 2024-25 **(B)**	Rs. Lakh	2,848.66	2,164.15
Net ARR to be recovered for LDC Charges 2025-26 **(C=A+B)**	Rs. Lakh	5,466.18	4,775.99
Contracted Capacity of Distribution licensees and Indian Railways and LTOA beneficiaries **(X)**	MW	35,897	35,897
Generators including thermal CPP/Solar/cogen **(Y)**	MW	22,797	22,797
Total Contracted Capacity **(Z= X+Y)**	MW	58,694	58,694
Monthly LDC Charges [C*10^5/(Z*12)]	**Rs/MW/Month**	**776.09**	**678.09**

**The Commission has considered the Gap of FY 2024-25 while determining the ARR of FY 2025-26.*

   (ii) The increase in LDC charges from Rs. 536.81/MW/Month, as approved in the Tariff Order dated 10.10.2024, to Rs. 678.09/MW/Month for FY 2025-26 is primarily on account of higher Net ARR, adjustment of gaps for FY 2023-24 and FY 2024-25.

   (iii) The Commission has directed UPSLDC to expedite SCADA/EMS upgradation, establish a Cyber Security Operation Centre (C-SOC), and to establish a structured framework for cybersecurity monitoring, regular vulnerability assessment, and incident response drills.

   (iv) UPSLDC shall ensure the availability of adequately trained and certified manpower as per CEA/Forum of Regulators norms. A skill-upgradation roadmap for JE-level & above staff must be submitted, and at least two specialised training workshops are to be conducted every year.

   (v) Further, UPSLDC is directed to create and maintain adequate state-level reserves for ancillary services. A detailed Advanced Distribution Management System (ADMS) roadmap for demand-side management regulation shall be submitted, with support from UPPCL and UPPTCL.

   (vi) UPSLDC is directed to conduct meetings of the State Power Committee regularly.

   The Tariff Order has been uploaded at **www.uperc.org**.

(Sumeet Kumar Agarwal)
08/09/2025
Secretary

प्रेस–नोट

दिनांक: 08 सितम्बर, 2025

उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (UPERC) ने यूपीएसएलडीसी हेतु वित्त वर्ष 2025-26 के लिए लोड डिस्पैच सेंटर (LDC) शुल्क निर्धारित किए

- **लोड डिस्पैच सेंटर (LDC) शुल्क ₹678.09 प्रति MW प्रति माह निर्धारित किया गया है जबकि ₹ 776.09 प्रति MW प्रति माह की माँग की गई थी।**
- **तकनीकी उन्नयन तथा साइबर हमलों के प्रति भेद्यता की जाँच हेतु निर्देश दिए गए हैं।**
- **नियुक्त कार्मिकों के कौशल-विकास एवं प्रमाणन (Certification) के लिए प्रोत्साहन प्रदान किए गए हैं।**

यूपीईआरसी ने यूपीएसएलडीसी हेतु वित्त वर्ष 2025-26 के लिए लोड डिस्पैच सेंटर (LDC) शुल्क निर्धारित किए

1. उत्तर प्रदेश स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर (UPSLDC) ने याचिका संख्या 2231/2025 दाखिल की थी, जिसमें वित्त वर्ष 2023-24 का ट्रू-अप, वित्त वर्ष 2024-25 की वार्षिक प्रदर्शन समीक्षा (APR) तथा वित्त वर्ष 2025-26 हेतु समेकित राजस्व आवश्यकता (ARR) एवं SLDC शुल्क का निर्धारण किया जाना प्रस्तावित था। इस याचिका को आयोग ने 24 जुलाई, 2025 को स्वीकार किया।

   इसके उपरांत, आयोग ने सार्वजनिक परामर्श की समुचित प्रक्रिया अपनाते हुए तथा 20 अगस्त, 2025 को सार्वजनिक सुनवाई आयोजित करने के बाद, वित्त वर्ष 2025-26 के लिए टैरिफ आदेश के अंतर्गत लोड डिस्पैच सेंटर (LDC) शुल्क निर्धारित कर दिए हैं, जो 08 सितम्बर, 2025 को जारी किए जा रहे हैं।

2. टैरिफ आदेश की मुख्य विशेषताएँ इस प्रकार हैं:

(i) आयोग ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ₹678.09 प्रति MW प्रति माह के मासिक LDC शुल्क को अनुमोदित किया है। आयोग ने 58,694 MW की contracted/tied up capacity को, जो उपयोगकर्ता दीर्घ/मध्यम अवधि के ओपन एक्सेस का उपभोग कर रहे हैं, ध्यान में रखा है। इसका विवरण नीचे दी गई तालिका में प्रस्तुत है:

वित्त वर्ष 2025-26 के लिए स्वीकृत एलडीसी शुल्क

Particulars	Units	FY 2025-26	
		Claimed by Petitioner	Approved by Commission
Annual Revenue Requirement (ARR) for FY 2025-26 **(A)**	Rs. Lakh	2,617.52	2,611.84
Adjustment Gap of FY 2023-24 & FY 2024-25 **(B)**	Rs. Lakh	2,848.66	2,164.15
Net ARR to be recovered for LDC Charges 2025-26 **(C=A+B)**	Rs. Lakh	5,466.18	4,775.99
Contracted Capacity of Distribution licensees and Indian Railways and LTOA beneficiaries **(X)**	MW	35,897	35,897
Generators including thermal CPP/Solar/cogen **(Y)**	MW	22,797	22,797
Total Contracted Capacity **(Z= X+Y)**	MW	58,694	58,694
Monthly LDC Charges [C*10^5/(Z*12)]	**Rs/MW/Month**	**776.09**	**678.09**

**आयोग ने वित्त वर्ष 2025-26 के एआरआर का निर्धारण करते समय वित्त वर्ष 2024-25 गैप को संज्ञान में लिया है.*

(ii) टैरिफ आदेश दिनांक 10.10.2024 में अनुमोदित ₹536.81 प्रति MW प्रति माह से बढ़कर वित्त वर्ष 2025-26 हेतु ₹678.09 प्रति MW प्रति माह LDC शुल्क वृद्धि का मुख्य कारण उच्च शुद्ध एआरआर (Net ARR), तथा वित्त वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 के अंतर (गैप) का समायोजन है।

(iii) आयोग ने यूपीएसएलडीसी को निर्देश दिया है कि वह शीघ्रातिशीघ्र SCADA/EMS उन्नयन करे, साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र (C-SOC) की स्थापना करे तथा साइबर सुरक्षा की निगरानी, नियमित भेद्यता आकलन (Vulnerability Assessment) और घटना प्रतिक्रिया अभ्यास (Incident Response Drills) हेतु एक संरचित ढाँचा विकसित करे।

(iv) यूपीएसएलडीसी यह सुनिश्चित करेगा कि सीईए/फोरम ऑफ रेगुलेटर्स के मानकों के अनुसार पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित एवं प्रमाणित जनशक्ति उपलब्ध हो। जेई-स्तर एवं उससे ऊपर के कर्मचारियों के लिए कौशल-वृद्धि (Skill Upgradation) का रोडमैप प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है तथा प्रत्येक वर्ष कम से कम दो विशेष प्रशिक्षण कार्यशालाएँ आयोजित की जाएँ।

(v) इसके अतिरिक्त, यूपीएसएलडीसी को निर्देशित किया जाता है कि वह सहायक सेवाओं (Ancillary Services) हेतु पर्याप्त राज्य-स्तरीय भंडार (Reserves) का सृजन एवं रखरखाव करे। माँग-पक्ष प्रबंधन विनियमन (Demand-Side Management Regulation) हेतु एक विस्तृत उन्नत वितरण प्रबंधन प्रणाली (ADMS) रोडमैप प्रस्तुत किया जाए, जिसमें यूपीपीसीएल (UPPCL) एवं यूपीपीटीसीएल (UPPTCL) का सहयोग लिया जाए।

(vi) यूपीएसएलडीसी को राज्य विद्युत समिति (State Power Committee) की बैठकें नियमित रूप से आयोजित करने के लिए निर्देशित किया जाता है।

टैरिफ आदेश www.uperc.org पर अपलोड कर दिया गया है।

08/09/2025

(सुमित कुमार अग्रवाल)
सचिव